

प्रेषक,

एन0रवि शंकर,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,  
उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0,  
देहरादून।

ऊर्जा विभाग

देहरादून: दिनांक: 17 जुलाई, 2006

विषय:

पंचायती राज संस्थाओं/सहकारी समितियों आदि के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत वितरण में स्थानीय प्रबन्धन हेतु नीति।

महोदय,

उक्त विषय के सम्बन्ध में उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल की 20वीं बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के साथ राज्य में विद्युत वितरण हेतु फ्रैन्चाइजी व्यवस्था लागू करने पर सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1- विद्युत का वितरण कार्य, जिसमें प्रचालन, अनुश्रवण तथा लागत वसूली सम्मिलित है, प्रारम्भ में चुनिन्दा ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती संस्थाओं, उपयोगकर्ता संगमों, सहकारी समितियों, गैर सरकारी संगठनों या विक्रय केन्द्रों (फ्रैन्चाइजी) को दिया जाए। बाद में धीरे-धीरे अनुभव के आधार पर सांगठनिक ढाँचे में यथोचित सुधार करते हुए इसका विस्तार सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों में किया जायेगा। प्रस्तावित व्यवस्था के निम्नलिखित मुख्य बिन्दु हैं:-

क- संस्था/निकायों का चयन व उनकी क्षमता

- (i) सम्बन्धित ग्राम के विद्युत उपभोक्ताओं की सहकारी समिति, ऊर्जा समिति (जो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अधीन पंजीकृत हों), ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, गैर सरकारी संगठन, अन्य सहकारी समितियाँ, स्थानीय व्यक्ति/उद्यमी अथवा विक्रय केन्द्र (फ्रैन्चाइजी) इस व्यवस्था हेतु चयनित किये जा सकते हैं।
- (ii) एक या एक से ज्यादा ग्रामों के समूह के लिए भी उक्तानुसार संस्था/निकाय का चयन किया जा सकता है।
- (iii) ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव द्वारा भी उनके द्वारा गैर सरकारी संगठनों का चयन कर कार्य लिया जा सकता है।

- (iv) ऐसी चयनित संस्था/निकायों द्वारा विद्युत सुरक्षा विभाग से प्रमाण-पत्र प्राप्त/प्रशिक्षित स्थानीय कर्मचारियों का चयन कर कार्य सम्पादन हेतु उपयोग किया जायेगा। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध होगा तथा प्रबन्धन भी स्थानीय स्तर पर हो सकेगा।
- (v) इस मध्य पंचायत संस्थाओं के सशक्तीकरण के लिए यथोचित विधिक, प्रशासनिक एवं प्रशिक्षण/क्षमता वृद्धि व्यवस्था की जायेगी।

ख- **कार्य क्षेत्र** इसके अन्तर्गत निम्न कार्य शामिल होंगे।

- (i) आवंटित क्षेत्र में विद्युत का वितरण।
- (ii) मीटरिंग और बिलिंग।
- (iii) LT/HT Line उपभोक्ता सेवा लाइनों व उपकरणों आदि का रख-रखाव।
- (iv) बिलिंग के सापेक्ष वसूली।
- (v) नये संयोजन देना/संयोजन विच्छेदन।
- (vi) वितरण ट्रांसफार्मर का रख-रखाव व इस पर स्थापित मीटर की UPCL के साथ संयुक्त रीडिंग।

ग- **गारंटी/प्रतिभूति**

सहकारी समित/ग्राम सभा/NGO/उपयोगकर्ता संघ आदि चयनित संस्था द्वारा उस क्षेत्र से वसूल किये जाने वाले औसत बिल के आधार पर दो महीने की धनराशि के बराबर राशि की बैंक गारन्टी/एफडी0आर0 के रूप में UPCL को प्रतिभूति के रूप में दी जायेगी।

घ- **राजस्व**

निगम (वितरण अनुज्ञापी) चयनित संस्था को UERC की नियत थोक कय दर पर विद्युत आपूर्ति करेगी। चयनित संस्था प्रत्येक माह की अवधि में निगम को वितरण ट्रांसफार्मर पर प्राप्त विद्युत के सापेक्ष नियत राजस्व जमा करने की कार्यवाही करेगा। प्रत्येक माह धनराशि जमा न होने अथवा एक माह के समतुल्य एरियर होने पर UPCL इस व्यवस्था को समाप्त कर नई व्यवस्था कर सकता है अथवा स्वयं वितरण व्यवस्था कर सकेगा।

च- चयनित संस्था/निकाय आवश्यक बीमा पॉलिसी लेंगे ताकि लगाये गये कार्मिकों व प्राप्त धनराशि आदि की सुरक्षा हो सके।

छ- यदि कोई निकाय/संस्था उचित वितरण व रख-रखाव सुनिश्चित करने में विफल होगी, ऐसी दशा में निगम को फ्रैन्चाइजी का अधिकार रद्द करने का अधिकार होगा। ऐसी दशा में निगम वितरण कार्य अपने हाथ में ले लेगा एवं अन्य व्यवस्था कर सकेगा।



- ज- चयनित संस्था/निकाय को आवंटित क्षेत्र की 15 दिन की अवधि के अन्तराल में उस क्षेत्र के अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता द्वारा निरीक्षण किया जायेगा। इस हेतु UPCL/लाईसैंसी द्वारा यथा आवश्यक भ्रमण चार्ट तैयार कर लिया जायेगा।
- झ- चयनित संस्था/निकाय को उसे आवंटित क्षेत्र में 100% घरों को विद्युत संयोजन देने का लक्ष्य इस प्रकार दिया जायेगा कि वर्ष 2009 तक यह कार्य पूर्ण हो सके। इस हेतु UPCL/लाईसैंसी द्वारा यथा आवश्यक सहयोग किया जायेगा।
- 2- उक्त बिन्दु-1 में इंगित व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में फ्रैन्चाइजी व्यवस्था को निम्नांकित शर्तों के साथ लागू किया जाए।
- (i) फ्रैन्चाइजी व्यवस्था को सहकारी संस्था, महिला मंगल दल, युवक मंगल दल, स्वयं सहायता समूह एवं ग्राम ऊर्जा समिति (जिसमें एक गाँव अथवा एक से अधिक गाँवों का समूह हो सकता है) के माध्यम से व्यवस्था करने पर बल दिया जाए।
  - (ii) गाँवों में जल संस्थान से सम्बन्धित बिलों के भुगतान की समस्या के निराकरण की दृष्टि से यह भी संस्तुति की गयी कि ग्राम स्तर अथवा एक से अधिक ग्राम समूह के स्तर पर ग्राम ऊर्जा एवं पेयजल समिति गठित करते हुए उनके माध्यम से फ्रैन्चाइजी व्यवस्था लागू की जा सकती है।
  - (iii) फ्रैन्चाइजी व्यवस्था प्रारम्भ में उन्हीं ग्रामों में लागू की जाए जिन गाँवों में तीन फेस लाइन, यथोचित क्षमता का ट्रांसफार्मर एवं ट्रांसफार्मर स्थल पर मीटर एवं मीटरिंग की व्यवस्था हो। इस व्यवस्था के लागू किये जाने की स्थिति में स्वयं सहायता समूह अथवा ग्राम ऊर्जा समिति से इस प्रकार का प्रमाण-पत्र लिया जाए कि उक्त सुविधाएँ वहाँ उपलब्ध हैं ताकि फ्रैन्चाइजी व्यवस्था में स्थानीय स्तर पर उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े।
  - (iv) राजस्व में हिस्सेदारी (revenue sharing) के साथ वितरण तंत्र की मरम्मत यथा-क्षतिग्रस्त/खराब ट्रांसफार्मर एवं लाइनों को बदलने तथा विस्तारीकरण आदि का कार्य UPCL द्वारा किया जाए।
  - (v) ग्राम ऊर्जा समितियों/फ्रैन्चाइजी व्यवस्था को UPCL द्वारा यथोचित प्रशिक्षण /उपकरण दिये जायेंगे। साथ ही रसीद बुक/रजिस्टर आदि भी उपलब्ध कराये जायेंगे।
  - (vi) प्रारम्भ में इस व्यवस्था को उच्च प्रौद्योगिकी के आधार पर न रखा जाए बल्कि इसे धीरे-धीरे लागू किये जाने पर विचार किया जाए।

- (vii) फ़ैन्चाइजी व्यवस्था में स्थानीय स्तर पर ऊर्जा समिति एवं उपभोक्ताओं को इस माध्यम से स्वतः प्रबन्धन के लिए तैयार किये जाने का अवसर एवं सुविधा प्राप्त हो।
- (viii) विद्युत संयोजन/विच्छेदन का अधिकार फ़ैन्चाइजी को उपलब्ध कराया जाए और नये कनेक्शन देने के सम्बन्ध में फ़ैन्चाइजी की संस्तुति के आधार पर कार्यवाही की जाए।
- (ix) ग्राम ऊर्जा समिति अथवा ग्राम ऊर्जा एवं पेयजल समिति के सम्बन्ध में पंचायतीराज अधिनियम (इसी प्रकार नगरीय क्षेत्र में नगर पालिका अधिनियम) में यथोचित संशोधन कर इन समितियों की व्यवस्था हेतु कार्यवाही की जाए।
- (x) सिक्थोरिटी एवं प्रतिभूति राशि दो माह से अधिक हेतु न रखी जाए।
- (xi) प्रारम्भ में फ़ैन्चाइजी व्यवस्था को केवल राजस्व वसूली के लिए मुख्य तौर पर रखा जाए जिसमें फ़ैन्चाइजी पर विद्युत आयात/निर्यात के मापन के आधार पर व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इस प्रकार की व्यवस्था में फ़ैन्चाइजी को उपलब्ध होने वाले कमीशन/धनराशि को काटते हुए फ़ैन्चाइजी द्वारा समय से UPCL को भुगतान की व्यवस्था की जाए।
- (xii) इस फ़ैन्चाइजी व्यवस्था में यह भी व्यवस्था रखी जाए कि अगले 05 (पॉच) वर्षों में विद्युत हानियां मानक स्तर पर करने की जिम्मेदारी फ़ैन्चाइजी की होगी और साथ ही अगले 03(तीन) वर्षों से सम्बन्धित क्षेत्र में शत-प्रतिशत घरों के विद्युतीकरण की जिम्मेदारी भी फ़ैन्चाइजी की होगी।

उक्त के सम्बन्ध में होने वाली प्रगति के बारे में प्रतिमाह नियमित रूप से टिप्पणी/आख्या शासन को प्रेषित की जाए।

भवदीय  
*N. Ravi Shankar*

(एन0रवि शंकर)  
प्रमुख सचिव

सख्या: 1012 /I/2006-06(3)/18/05/तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित-

- 1- सचिव, मा0 मुख्य मंत्री को मा0 मुख्य मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 2- निजी सचिव-मा0 ऊर्जा राज्य मंत्री को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 3- सचिव, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली।



- 4- निजी सचिव-मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के संज्ञानार्थ।
- 5- निजी सचिव-अपर मुख्य सचिव को अपर मुख्य सचिव के संज्ञानार्थ।
- 6- निजी सचिव-अवस्थापना विकास आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, वित्त को प्रमुख सचिव के संज्ञानार्थ।
- 7- महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
- 8- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
- 9- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
- 10- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, आर0ई0सी0, नई दिल्ली।
- 11- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल जल विद्युत निगम लि0, देहरादून।
- 12- प्रबन्ध निदेशक, पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तरांचल लि0, देहरादून।
- 13- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमाँयू मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
- 14- समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
- 15- सचिव, उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग।
- 16- विद्युत निरीक्षक, उत्तरांचल, हल्द्वानी, नैनीताल।
- 17- निदेशक, उरेडा, देहरादून।
- 18- एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून को ऊर्जा विभाग की वैबसाइट हेतु।
- 19- गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से

(डा0एम0सी0जोशी)  
अपर सचिव

- 4- निजी सचिव-मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के संज्ञानार्थ।
- 5- निजी सचिव-अपर मुख्य सचिव को अपर मुख्य सचिव के संज्ञानार्थ।
- 6- निजी सचिव-अवस्थापना विकास आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, वित्त को प्रमुख सचिव के संज्ञानार्थ।
- 7- महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
- 8- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
- 9- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
- 10- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, आर0ई0सी0, नई दिल्ली।
- 11- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल जल विद्युत निगम लि0, देहरादून।
- 12- प्रबन्ध निदेशक, पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तरांचल लि0, देहरादून।
- 13- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमाँयू मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
- 14- समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
- 15- सचिव, उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग।
- 16- विद्युत निरीक्षक, उत्तरांचल, हल्द्वानी, नैनीताल।
- 17- निदेशक, उरेडा, देहरादून।
- ✓ 18- एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून को ऊर्जा विभाग की वैबसाइट हेतु।
- 19- गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से



(डा0एम0सी0जोशी)  
अपर सचिव